National Research Journal of Social Sciences
Volume-11, Issue-1, January-June 2026
PP: 403-411

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

ट्रिंकोमाली बंदरगाह विकास: भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा

देवेंद्र कुमार

शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, (बिहार)

प्रोफेसर मुनेश्वर यादव

शोध निर्देशक, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,

ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

ट्रिंकोमाली बंदरगाह का रणनीतिक और आर्थिक विकास भारत–श्रीलंका संबंधों में उभरते नए आयामों को प्रतिबिंबित करता है। अपनी असाधारण प्राकृतिक गहराई और सामरिक स्थिति के कारण विश्व के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में गिने जाने वाला ट्रिंकोमाली, हिंद महासागर क्षेत्र में तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में ट्रिंकोमाली का विकास केवल सुरक्षा-केन्द्रित दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि 'कोलंबो–ट्रिंकोमाली आर्थिक गलियारे', ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी और औद्योगिक अवसंरचना सहयोग के माध्यम से व्यापक आर्थिक अंतरसंबंधों की दिशा में उन्मुख है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से बंदरगाह की कार्गो क्षमता, तेल टैंकों के प्रबंधन तथा 2050 तक संभावित व्यापार विस्तार का संकेत मिलता है। साथ ही, स्थानीय जातीय राजनीति, भूमि स्वामित्व विवाद और प्रशासनिक चुनौतियाँ इस परियोजना की प्रगति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के ऐतिहासिक संदर्भ से लेकर 2022 के तेल टैंक फार्म पुनरुद्धार समझौते तक, यह आलेख यह स्पष्ट करता है कि कैसे भारत अपनी 'पड़ोस प्रथम' नीति के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेष रूप से हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी में चीनी निवेश, को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है ।

शब्द कुंजी: ट्रिंकोमाली बंदरगाह विकास, हिंद-प्रशांत भू-राजनीति, ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म, पड़ोस प्रथम नीति, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी, नीली अर्थव्यवस्था

परिचय

हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक संरचना में श्रीलंका के पूर्वी तट पर अवस्थित ट्रिंकोमाली बंदरगाह एक निर्णायक भू-रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरता है, जहाँ इतिहास, भौगोलिक विशेषताएँ और समकालीन कूटनीति परस्पर अंतर संबद्ध दिखाई देती हैं। अपनी असाधारण प्राकृतिक गहराई और विस्तृत जलक्षेत्र के कारण ट्रिंकोमाली को लंबे समय से वैश्विक शक्तियों द्वारा बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव स्थापित करने के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता रहा है। ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन द्वारा इसे "विश्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह" कहा जाना तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल नेवी के लिए इसका एक सुदृढ़ सामरिक अड्डे के रूप में उपयोग, इसकी ऐतिहासिक सामरिक प्रासंगिकता को पुष्ट करता है।

समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में ट्रिंकोमाली का महत्व पुनः रेखांकित हुआ है, विशेषकर भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना और चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के बीच उभरते शक्ति-संतुलन की पृष्ठभूमि में। यह

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

बंदरगाह केवल सामरिक प्रतिस्पर्धा का स्थल नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति-प्रक्षेपण और समुद्री मार्गों की सुरक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

भारत के लिए, ट्रिंकोमाली का विकास उसकी 'सागर' पहल का एक जीवंत उदाहरण है। यह साझेदारी केवल ईंट-पत्थर के बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक एकीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता का एक एकीकृत मॉडल है। 2022 में श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा दी गई मानवीय और वित्तीय सहायता ने दोनों देशों के बीच विश्वास की एक नई नींव रखी है, जिसका केंद्र ट्रिंकोमाली बना है। यह आलेख ट्रिंकोमाली बंदरगाह के विकास को भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी के व्यापक संदर्भ में देखता है, जहाँ आर्थिक लाभ और सुरक्षा चिंताएं एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम यह विश्लेषण करेंगे कि कैसे यह बंदरगाह न केवल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बन सकता है, बल्कि भारत के दक्षिणी तट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक प्रहरी के रूप में भी कार्य कर सकता है।

ट्रिंकोमाली का ऐतिहासिक और भौगोलिक परिदृश्य

ट्रिंकोमाली बंदरगाह की विशिष्ट भौगोलिक संरचना इसे हिंद महासागर के अन्य प्रमुख बंदरगाहों से भिन्न पहचान प्रदान करती है। श्रीलंका के उत्तर–पूर्वी तट पर अवस्थित यह बंदरगाह एक विस्तृत प्राकृतिक खाड़ी के रूप में विकसित हुआ है, जिसकी संरचना बहु-स्तरीय जलक्षेत्र, सुरक्षित आंतरिक लंगरगाहों और गहरे समुद्री मार्गों से युक्त है। इसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 25 मीटर तक मानी जाती है, जो इसे निरंतर ड्रेजिंग की आवश्यकता के बिना अति-वृहद तेल टैंकरों, कंटेनर जहाजों तथा भारी मालवाहक पोतों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। यही विशेषता इसे दीर्घकालिक वाणिज्यिक उपयोग के साथ-साथ सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत सक्षम बनाती है। तांतरे एवं अन्य (2025) के विश्लेषण के अनुसार, बंदरगाह की गहराई और भू-आकृतिक संरचना आधुनिक नौसैनिक अभियानों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह परमाणु पनडुब्बियों के विवेकपूर्ण और सुरक्षित संचालन की संभावनाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार, ट्रिंकोमाली की भौगोलिक विशेषताएँ इसे केवल एक वाणिज्यिक केंद्र नहीं, बल्कि सामरिक अवसंरचना के रूप में भी स्थापित करती हैं।[1]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, ट्रिंकोमाली पर नियंत्रण हेतु वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का दीर्घ इतिहास रहा है। 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य ने इस बंदरगाह का उपयोग बंगाल की खाड़ी और मलय क्षेत्र के व्यापारिक समुद्री मार्गों पर प्रभाव स्थापित करने के लिए किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश नौसेना ने बर्मा और चीन के साथ अपने सैन्य अभियानों के दौरान इसे एक अग्रिम नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, विशेषकर सिंगापुर के पतन के उपरांत, ट्रिंकोमाली हिंद महासागर में मित्र राष्ट्रों के लिए एक प्रमुख लंगर स्थल बन गया। 1942 में जापानी हवाई हमलों के बावजूद इसकी सामरिक उपयोगिता अक्षुण्ण बनी रही, जिससे इसकी संरचनात्मक दृढ़ता और सामरिक महत्ता स्पष्ट होती है।[2]

आधुनिक काल में भारत के रणनीतिक चिंतन में ट्रिंकोमाली का औपचारिक समावेश 1987 के भारत–श्रीलंका समझौते के माध्यम से हुआ। इस समझौते के अंतर्गत आदान-प्रदान किए गए पत्रों में यह सुनिश्चित किया गया कि श्रीलंका अपने किसी भी बंदरगाह, विशेषतः ट्रिंकोमाली, का उपयोग भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। यह प्रावधान आज भी भारत की समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा नीति का एक

[1] Tantray, T. L., Sudhakar, R., & Charak, S. S. (2025). Trincomalee Harbour in the Indo-Pacific: Strategic significance and contemporary geopolitical implications for India. Journal of Maritime Research, 22(1), 137–145.

[2] ब्रूस्टर, डी. (2014). इंडियाज ओशन: द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिड फॉर रीजनल लीडरशिप . रूटलेज

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

आधारभूत तत्व बना हुआ है, विशेषकर ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र में बाह्य शक्तियों, विशेषकर चीन, की उपस्थिति और प्रभाव में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

भू-राजनीतिक विमर्श और भारत की सुरक्षा

हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती शक्ति-प्रतिस्पर्धा ने तथाकथित 'सुरक्षा दुविधा' को तीव्र किया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रिंकोमाली बंदरगाह भारत की समुद्री रणनीति के केंद्र में आ गया है। क्षेत्रीय संतुलन पर चीन की सक्रियता का प्रभाव विशेष रूप से तब स्पष्ट हुआ जब हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीनी नियंत्रणाधीन पट्टे पर दिया गया तथा कोलंबो पोर्ट सिटी जैसी विशाल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में चीन की व्यापक भागीदारी सामने आई। इन घटनाक्रमों ने भारत की सामरिक समुदाय में यह आशंका उत्पन्न की कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति केवल आर्थिक निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक भू-राजनीतिक प्रभाव-स्थापना की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि इन बंदरगाहों का उपयोग भारत की परमाणु, अंतरिक्ष तथा अनुसंधान-संबंधी परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए संभावित 'लुकआउट पोस्ट' के रूप में किया जा सकता है, जिससे समुद्री सुरक्षा परिवेश और अधिक जटिल हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में भारत ने ट्रिंकोमाली के विकास को एक संतुलनकारी रणनीति के रूप में परिकल्पित किया है। तांतरे एवं अन्य (2025) के अनुसार, ट्रिंकोमाली में भारत की रुचि उसकी विस्तृत तटरेखा की सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्रमुख समुद्री संचार लाइनों की निकटता से जुड़ी हुई है। इस दृष्टि से ट्रिंकोमाली केवल व्यापारिक गतिविधियों का स्थल नहीं, बल्कि एक 'रणनीतिक तलहटी' के रूप में देखा जाता है, जो क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर भारत की उपस्थिति और प्रभाव को सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है।[3]

भारत–श्रीलंका संयुक्त वक्तव्यों (2022–2024) में दोनों देशों ने साझा समुद्री सुरक्षा हितों को स्वीकार करते हुए एक मुक्त, खुले और सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत की 'महासागर' पहल इसी व्यापक सुरक्षा अवधारणा का विस्तार है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, सामूहिक सुरक्षा और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ट्रिंकोमाली इस पहल का एक प्रमुख कार्यान्वयन-स्थल बनकर उभरा है, जहाँ भारत बंदरगाह अवसंरचना में निवेश के साथ-साथ रक्षा-सहयोग को भी सुदृढ़ कर रहा है। श्रीलंका की नौसेना को फ्लोटिंग डॉक उपलब्ध कराना, जिससे बड़े जहाजों का रखरखाव स्थानीय स्तर पर संभव हो सके, इस सामरिक साझेदारी की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।

आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा

ट्रिंकोमाली बंदरगाह के विकास में सर्वाधिक निर्णायक आयाम उसका संभावित 'ऊर्जा हब' के रूप में उभार है, जिसने भारत–श्रीलंका आर्थिक संबंधों को एक नए संरचनात्मक आधार पर स्थापित किया है। 2022 में उत्पन्न अभूतपूर्व आर्थिक संकट के पश्चात श्रीलंका की ऊर्जा आपूर्ति, विदेशी मुद्रा भंडार और ईंधन वितरण प्रणाली पर गंभीर दबाव उत्पन्न हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय स्थिरता का केंद्रीय प्रश्न बनकर उभरी। भारत ने इस परिस्थिति को केवल तात्कालिक सहायता तक सीमित न रखकर दीर्घकालिक आर्थिक अंतर निर्भरता को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पारस्परिक लाभ पर आधारित ऐसी संरचना विकसित करना था, जिसमें अवसंरचनात्मक सहयोग और ऊर्जा प्रबंधन दोनों देशों के रणनीतिक हितों को संतुलित रूप से आगे बढ़ा सकें।

ट्रिंकोमाली स्थित तेल टैंक फार्म, जिसे 'चाइना बे ऑयल टैंक फार्म' के नाम से भी जाना जाता है, इस उभरती साझेदारी का प्रमुख प्रतीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में निर्मित इन 99 विशाल भंडारण टैंकों की संयुक्त

[3] https://www.lankaweb.com/news/items/2026/02/15/policy-position-paper/.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

क्षमता 1.2 मिलियन टन से अधिक आंकी जाती है। इतनी व्यापक भंडारण क्षमता श्रीलंका को दक्षिण एशिया के एक संभावित पेट्रोलियम वितरण एवं पुनः-निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, यह संरचना क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन और आपातकालीन भंडारण की सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे समुद्री व्यापार मार्गों पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को स्थिरता मिल सकती है।

2022 में संपन्न समझौते के अंतर्गत इन टैंकों के पुनरुद्धार और प्रबंधन को एक त्रिपक्षीय ढांचे में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें निवेश, संचालन और वितरण संबंधी दायित्वों को संस्थागत रूप दिया गया है। यह व्यवस्था केवल परिसंपत्तियों के पुनःसक्रियकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा अवसंरचना के आधुनिकीकरण, भंडारण क्षमता के अनुकूलन और संभावित औद्योगिक उपयोग के विस्तार की दिशा में भी अग्रसर है। इस प्रकार, ट्रिंकोमाली का ऊर्जा आयाम भारत–श्रीलंका संबंधों में आर्थिक साझेदारी, रणनीतिक विश्वास और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के समेकित मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।

तालिका 1: ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म का वितरण (2022 समझौता)

घटक	टैंकों की संख्या	संचालक/स्वामित्व संरचना	मुख्य उद्देश्य
निचला टैंक फार्म	14	लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (LIOC)	वर्तमान वाणिज्यिक संचालन और बंकरिंग
संयुक्त उद्यम	61	ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड (TPTL)	भारत (49%) और श्रीलंका (51%) का संयुक्त विकास
राष्ट्रीय कोटा	24	सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (CPC)	श्रीलंका की घरेलू पेट्रोलियम जरूरतों की आपूर्ति
कुल क्षमता	**99**	**~1.2 मिलियन मेट्रिक टन**	**क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक भंडार**

स्रोत:https://idsa.in/askanexpert/vineet-ravindran-asked-how-does-the-trincomalee-oil-farm-deal-benefit-india-why-is-trincomalee-important-for-india.[4]

यह समझौता 50 वर्षों के लिए किया गया है और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र को एक क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन हब के रूप में विकसित करना है। इसके पूरक के रूप में, भारत ने चेन्नई और ट्रिंकोमाली के बीच एक द्विदिश पाइपलाइन का प्रस्ताव दिया है, जो प्रति वर्ष 3.5 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन कर सकती है। यह पाइपलाइन न केवल परिवहन लागत को कम करेगी, बल्कि संकट के समय दोनों देशों के लिए एक 'रणनीतिक भंडार' के रूप में भी कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी इस साझेदारी का एक और स्तंभ है। $1.2 बिलियन की अनुमानित लागत वाली एक undersea बिजली केबल परियोजना पर चर्चा चल रही है, जो श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में उत्पन्न होने वाली सौर और पवन ऊर्जा को भारत के दक्षिणी ग्रिड से जोड़ेगी। यह पहल श्रीलंका के 2030 तक 70% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है ।

[4]https://idsa.in/askanexpert/vineet-ravindran-asked-how-does-the-trincomalee-oil-farm-deal-benefit-india-why-is-trincomalee-important-for-india.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

बंदरगाह बुनियादी संरचना और व्यापार डेटा विश्लेषण

ट्रिंकोमाली बंदरगाह का वर्तमान परिचालन ढांचा मुख्यतः थोक कार्गो (bulk cargo) के प्रबंधन पर केंद्रित है, जो इसे श्रीलंका के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित करता है। एशियाई विकास बैंक (ADB) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, बंदरगाह ने वर्ष 2016 में लगभग 3.2 मिलियन टन माल का प्रबंधन किया, जो 2017 में बढ़कर 3.89 मिलियन टन तक पहुँच गया। यह वृद्धि बंदरगाह की परिचालन क्षमता में क्रमिक विस्तार और घरेलू औद्योगिक मांग में वृद्धि का संकेत देती है। अवसंरचनात्मक दृष्टि से बंदरगाह में 'अशरफ जेटी', 'मुड कोव' तथा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित टर्मिनल जैसे टोक्यो सीमेंट और प्राइमा फ्लोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुविधाएँ विशेषीकृत थोक कार्गो के कुशल प्रबंधन को संभव बनाती हैं और बंदरगाह की समग्र लॉजिस्टिक क्षमता को सुदृढ़ करती हैं।

तालिका 2: ट्रिंकोमाली बंदरगाह कार्गो थ्रूपुट डेटा (2010-2017)

कार्गो प्रकार (हजार टन में)	2010	2013	2016	2017	वृद्धि का मुख्य कारक
क्लिनकर (थोक)	738	1,124	1,490	1,678	सीमेंट उद्योग की मांग (टोक्यो सीमेंट)
गेहूं (थोक)	714	885	867	1,090	प्राइमा फ्लोर फैसिलिटी का विस्तार
तरल थोक (ईंधन)	191	256	238	417	LIOC के बढ़ते संचालन
कोयला	85	102	95	110	ऊर्जा उत्पादन की जरूरतें
कुल डिस्चार्ज माल	1,960	2,450	2,820	3,120	आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि

स्रोत: https://archive.veriteresearch.org/handle/456/6995?show=full.[5]

उपरोक्त आँकड़े संकेत करते हैं कि 2010 से 2017 के मध्य थोक वस्तुओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेषतः क्लिनकर और गेहूं जैसे औद्योगिक एवं उपभोग-संबंधी कार्गो में। तरल थोक (ईंधन) की वृद्धि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग और लंका इंडियन ऑयल कंपनी के विस्तारित संचालन को परिलक्षित करती है। भविष्य की विकास योजनाएँ बंदरगाह को पारंपरिक लोडिंग–अनलोडिंग केंद्र से आगे बढ़ाकर एक समेकित औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब में रूपांतरित करने पर केंद्रित हैं। 2050 तक के पूर्वानुमानों में कंटेनर यातायात के उभरने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि वर्तमान में यह शून्य के स्तर पर है। यह संभावित परिवर्तन ट्रिंकोमाली को बहु-आयामी समुद्री व्यापार केंद्र में परिवर्तित कर सकता है।

तालिका 3: वस्तु-वार व्यापार पूर्वानुमान (2050 लक्ष्य)

वस्तु श्रेणी	2016 आधार (हजार टन)	2050 अनुमान (हजार टन)	संभावित विकास पहल

[5] https://archive.veriteresearch.org/handle/456/6995?show=full.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

अनाज/गेहूं	867	1,709	नए प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात केंद्र
सीमेंट/क्लिनकर	1,490	3,113	निर्माण सामग्री हब के रूप में विकास
परिष्कृत तेल	238	1,358	तेल टैंक फार्म और पाइपलाइन एकीकरण
कंटेनर (TEUs)	0	112,000	समर्पित कंटेनर टर्मिनल का निर्माण
नई वस्तुएं (उर्वरक/इल्मेनाइट)	0	2,236	खनिज प्रसंस्करण और कृषि लॉजिस्टिक्स

स्रोत:https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50184/50184-001-tacr-en_12.pdf[6]

उपरोक्त प्रक्षेपण इंगित करते हैं कि बंदरगाह का भविष्य केवल पारंपरिक थोक व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मूल्य-वर्धित औद्योगिक गतिविधियों के साथ समेकित होगा। अनाज और गेहूं की श्रेणी में संभावित वृद्धि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात केंद्रों की स्थापना से जुड़ी है, जो कृषि-आधारित उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ सकती है। इसी प्रकार, सीमेंट और क्लिनकर की मात्रा में वृद्धि ट्रिंकोमाली को क्षेत्रीय निर्माण सामग्री वितरण केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति को दर्शाती है। परिष्कृत तेल के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान तेल टैंक फार्म के आधुनिकीकरण तथा पाइपलाइन एकीकरण परियोजनाओं से संबंधित है, जो ऊर्जा लॉजिस्टिक्स को अधिक कुशल और लागत-प्रभावी बना सकते हैं। कंटेनर यातायात, जो 2016 में शून्य था, 2050 तक 112,000 TEUs तक पहुँचने का अनुमान दर्शाता है कि बंदरगाह को बहुउद्देशीय समुद्री व्यापार केंद्र में परिवर्तित करने की स्पष्ट योजना है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 'अशरफ जेटी' के विस्तार तथा एक नए गहरे पानी की तेल जेटी के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का आधुनिकीकरण जैसे 'टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम' और 'हार्बर मास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' बंदरगाह संचालन की दक्षता, पारदर्शिता और वास्तविक समय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य माना गया है।

कोलंबो–ट्रिंकोमाली आर्थिक गलियारा

एशियाई विकास बैंक के सहयोग से प्रस्तावित 'कोलंबो–ट्रिंकोमाली आर्थिक गलियारा' श्रीलंका की क्षेत्रीय आर्थिक संरचना को पुनर्संतुलित करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल के रूप में उभरता है। यह परियोजना देश के पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों के मध्य अवसंरचनात्मक तथा औद्योगिक एकीकरण स्थापित करने का उद्देश्य रखती है। प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम गलियारा कोलंबो के परिधीय क्षेत्रों से आरंभ होकर कुरुनेगाला, दांबुला और हबरना जैसे आंतरिक शहरी केंद्रों से गुजरते हुए ट्रिंकोमाली तक विस्तृत होगा। इस प्रकार, यह गलियारा तटीय और आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य एक समेकित संपर्क-संरचना विकसित करने का प्रयास करता है।[7]

[6] https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50184/50184-001-tacr-en_12.pdf.

[7] तकनीकी रिपोर्ट (Technical Report): मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस सॉल्यूशंस (MTBS). (2019). श्रीलंका नेशनल पोर्ट मास्टर प्लान: ट्रिंकोमाली पोर्ट डेवलपमेंट (वॉल्यूम 3, भाग 1-4). एशियाई विकास बैंक (ADB).

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

CTEC का केंद्रीय उद्देश्य श्रीलंका को वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रभावी रूप से समाविष्ट करना तथा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण गतिविधियों को एकीकृत कर निर्यात-उन्मुख औद्योगिक विकास को गति देने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, यह गलियारा भारत के पूर्वी औद्योगिक गलियारे के साथ एक पूरक संरचना के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में वृद्धि संभव है। CTEC के अंतर्गत प्रस्तावित औद्योगिक नोड्स कृषि-प्रसंस्करण, विनिर्माण तथा लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर केंद्रित होंगे। इन नोड्स का उद्देश्य मूल्य-वर्धित उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा आंतरिक क्षेत्रों को निर्यात तंत्र से जोड़ना है। इस व्यापक ढांचे में ट्रिंकोमाली बंदरगाह एक प्रमुख निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में उभर सकता है, जो औद्योगिक उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में सहायक होगा।

सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियां

ट्रिंकोमाली का विकास चुनौतियों से रहित नहीं है। स्थानीय जातीय राजनीति और भूमि स्वामित्व के मुद्दे इस साझेदारी के लिए एक गंभीर बाधा बने हुए हैं। ट्रिंकोमाली जिला ऐतिहासिक रूप से तमिल और मुस्लिम समुदायों का केंद्र रहा है, और यहाँ श्रीलंका सरकार द्वारा "सिंहलीकरण" और सैन्यीकरण के माध्यम से जनसांख्यिकी बदलने के आरोप लगे हैं। ऑकलैंड इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट (2024) के अनुसार, ट्रिंकोमाली के छह मंडलों में गहन भूमि अधिग्रहण देखा गया है, जहाँ पारंपरिक तमिल और मुस्लिम आबादी की आजीविका प्रभावित हुई है।[8]

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रवादी भावनाएं अक्सर भारत के साथ बड़े समझौतों को संप्रभुता के लिए खतरा मानती हैं। श्रीलंका की 'जनता विमुक्ति पेरामुना' जैसी पार्टियों ने 2022 के तेल टैंक फार्म समझौते का कड़ा विरोध किया था। यद्यपि वर्तमान सरकार ने आर्थिक वास्तविकता को देखते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन "इंडो-फोबिया" का तत्व अभी भी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।[9]

पर्यावरणीय मोर्चे पर, ट्रिंकोमाली की पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है। बंदरगाह विकास और औद्योगिक गतिविधियों के लिए 'रणनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन' और 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' की आवश्यकता है। समुद्र के नीचे पाइपलाइन और बिजली केबलों के निर्माण से समुद्री जैव विविधता और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा। जलवायु परिवर्तन और मानसून के बदलते पैटर्न भी बंदरगाह संचालन और बुनियादी ढांचे की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं।[10]

क्षेत्रीय सहयोग और बिम्सटेक

ट्रिंकोमाली का महत्व केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिम्सटेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के तहत, ट्रिंकोमाली को दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीच एक समुद्री सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है ।

[8] ऑकलैंड इंस्टीट्यूट. (2024). ट्रिंकोमाली रिपोर्ट: डिटरमाइनिंग द लैंड ग्रैबिंग एंड मिलिटराइजेशन इन श्रीलंका.

[9] तमिल गार्डियन. (2025, 16 जनवरी). ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म वेंचर मूव्स फॉरवर्ड डिस्पाइट पास्ट अपोजिशन.

[10] कपलान, आर. डी. (2011). मानसून: द इंडियन ओशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर. रैंडम हाउस.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

बिम्सटेक के तहत ट्रिंकोमाली की भूमिका

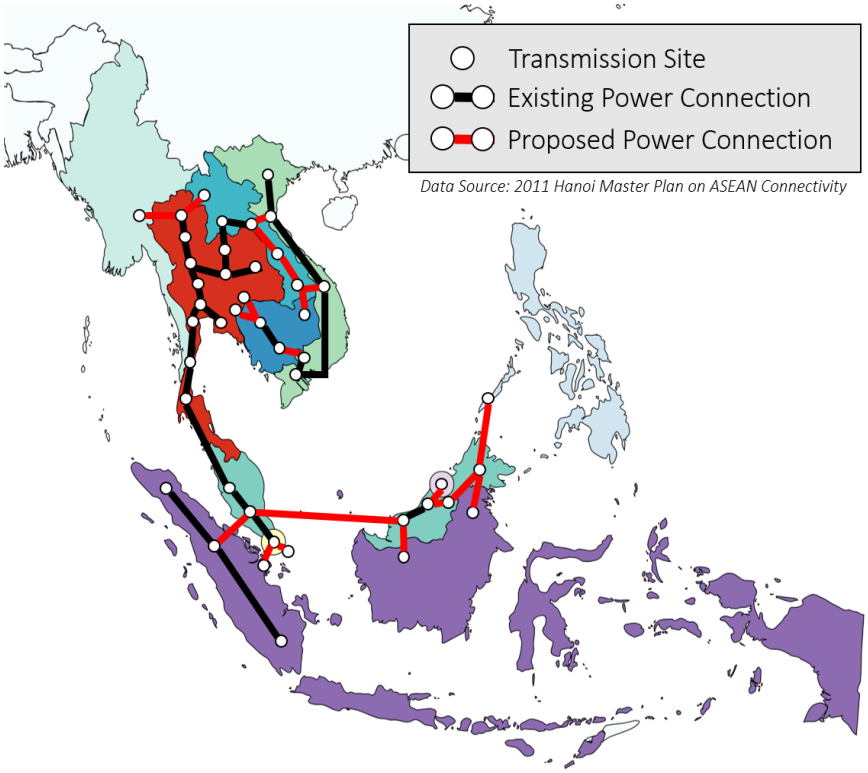

1. **समुद्री संपर्क:** बंगाल की खाड़ी के चारों ओर के बंदरगाहों के बीच माल की आवाजाही को सुगम बनाना और जहाजों के आवागमन के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी पर बातचीत करना।

2. **ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी:** बिम्सटेक के तहत 'इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन' के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का आदान-प्रदान करना, जिसमें ट्रिंकोमाली एक नोड के रूप में कार्य करेगा।

3. **बहु-मोडल परिवहन:** 267 परियोजनाओं वाले बिम्सटेक मास्टर प्लान के साथ समन्वय करना ताकि बंदरगाह को सड़क और रेल नेटवर्क के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा जा सके।

4. भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और 'सागर' (SAGAR) विजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चीन के "ऋण-भारी" मॉडल के मुकाबले एक निवेश-आधारित और स्थायी साझेदारी मॉडल प्रस्तुत करना है। ट्रिंकोमाली का विकास इसी 'वैकल्पिक मॉडल' की सफलता का परीक्षण है।

परिणाम

इस शोध के विश्लेषण से निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं:-

1. **रणनीतिक संतुलन:** ट्रिंकोमाली बंदरगाह में भारत की सक्रिय भागीदारी ने हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की एक विश्वसनीय संरचना निर्मित की है। यह उपस्थिति क्षेत्र में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के प्रभाव को सीमित करने में सहायक सिद्ध हुई है तथा समुद्री सुरक्षा परिवेश में एक संतुलनकारी तत्व के रूप में कार्य करती है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

2. **ऊर्जा अंतर्निर्भरता:** तेल टैंक फार्म के संयुक्त पुनरुद्धार, पाइपलाइन समेकन तथा संभावित ग्रिड कनेक्टिविटी ने भारत और श्रीलंका के मध्य एक संरचित 'ऊर्जा सुरक्षा गलियारा' विकसित किया है। यह व्यवस्था आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाती है और आपात अथवा आर्थिक संकट की परिस्थितियों में दोनों देशों के लिए पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करती है।

3. **आर्थिक विविधीकरण:** ट्रिंकोमाली का स्वरूप अब केवल एक सामरिक या सैन्य बंदरगाह तक सीमित नहीं रहा है। यह कोलंबो–ट्रिंकोमाली आर्थिक गलियारे तथा अपतटीय इंजीनियरिंग हब की अवधारणा के अंतर्गत विनिर्माण, कृषि-प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के समेकित केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक आधार का विस्तार संभव हुआ है।

4. **ऋण-जाल का विकल्प:** भारत द्वारा अपनाया गया निवेश-आधारित सहयोग मॉडल, जिसमें लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता तथा परियोजना-विशिष्ट अनुदान सम्मिलित हैं, श्रीलंका के लिए ऋण-निर्भर विकास मॉडल का एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और संरचनात्मक सुधार को प्रोत्साहित करता है।

5. **क्षेत्रीय एकीकरण:** बिम्सटेक और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ समन्वय ने ट्रिंकोमाली को एक उभरते वैश्विक व्यापारिक नोड के रूप में स्थापित किया है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य संपर्क-संरचना को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

ट्रिंकोमाली बंदरगाह का विकास भारत–श्रीलंका आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के उभरते प्रतिमान का द्योतक है। यह पहल भू-राजनीतिक आवश्यकताओं और भू-आर्थिक संभावनाओं के संगम को मूर्त रूप देती है। एक ओर ट्रिंकोमाली भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना में एक सुदृढ़ प्रहरी की भूमिका निभाता है, तो दूसरी ओर यह श्रीलंका की आर्थिक पुनर्प्राप्ति, ऊर्जा स्थिरता और औद्योगिक विस्तार के लिए संभावित शक्ति-केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस प्रकार, बंदरगाह का विकास द्विपक्षीय हितों को संतुलित करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता केवल अवसंरचनात्मक निवेश पर निर्भर नहीं करेगी। आवश्यक है कि दोनों देश 'पिछड़े संबंधों' को सशक्त करें, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करें तथा तटीय समुदायों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को प्राथमिकता दें। स्थानीय राजनीतिक असहमति, भूमि-संबंधी विवाद और जातीय संवेदनशीलताओं का समाधान पारदर्शी संवाद, सहभागी नियोजन और समावेशी विकास रणनीतियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

भविष्य की दृष्टि से ट्रिंकोमाली को मात्र द्विपक्षीय परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक हिंद–प्रशांत संरचना के केंद्रीय घटक के रूप में देखा जाना अपेक्षित है। 'ब्लू इकोनॉमी', हरित ऊर्जा और स्मार्ट पोर्ट प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से यह बंदरगाह भारत और श्रीलंका के संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि का प्रतीक बन सकता है।

© Copyright @ Authors